2006(9) eILR(PAT) SC 1

राम प्रवेश सिंह और अन्य

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

22 सितंबर, 2006

[बी.पी. सिंह और आर. वी. रवींद्रन, न्यायमूर्तिगण]

सेवा विधि :

विद्युत अधिनियम, 1910 - धारा 3 - सेवाओं का अवशोषण - एक सोसाइटी का समापन और विद्युत बोर्ड के साथ उनके उपक्रमों का विलय - उसके कर्मचारियों का अवशोषण न होना - चुनौती दी गई - कर्मचारियों की सेवाओं को अवशोषित करने का बोर्ड का दायित्व - अभिनिर्धारितः बोर्ड की ओर से संविदात्मक, वैधानिक या न्यायसंगत विचारों पर कर्मचारियों की सेवाओं को अवशोषित करने का कोई दायित्व नहीं था - एक उपक्रम के हस्तांतरण का स्वाभाविक परिणाम, जब तक कि कर्मचारियों की सेवा जारी रखने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान न हो, रोजगार की समाप्ति और क्षतिपूर्ति देने का नियोक्ता का दायित्व है - औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 - धारा 25-एफ एफ.

प्रशासनिक विधि - वैध अपेक्षा का सिद्धांत - प्रकृति और दायरा - अभिनिर्धारितः वैध अपेक्षा कोई कानूनी अधिकार नहीं है - यह एक लाभ, राहत या उपाय की अपेक्षा है जो सामान्य रूप से किसी वादे या स्थापित प्रथा से प्रवाहित हो सकती है - अपेक्षा वैध, उचित, तार्किक और मान्य होनी चाहिए - यह प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा के लिए न्यायालयों द्वारा

बनाई गई एक अवधारणा है - यह प्रकृति में प्रक्रियात्मक है - भले ही इसे सिद्ध कर दिया जाए, यह हमेशा अपेक्षा करने वाले को राहत का हकदार नहीं बनाती - जनहित, नीति में बदलाव, अपेक्षा करने वाले का आचरण या निर्णय लेने वाले द्वारा दिया गया कोई अन्य मान्य या सद्भावनापूर्ण कारण, वैध अपेक्षा को नकारने के लिए पर्याप्त हो सकता है - स्थापित प्रथा पर आधारित सिद्धांत का आह्वान प्राधिकरण से असंबंधित पूर्ण अजनबी व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता है।

एक सहकारी समिति का परिसमापन किया गया और बिहार विद्युत बोर्ड के साथ विलय कर दिया गया। चूँकि बोर्ड ने सोसाइटी के कर्मचारियों की सेवाओं को अवशोषित नहीं किया, इसलिए उसके अपीलकर्ता कर्मचारियों ने बोर्ड को उन्हें अवशोषित करने का निर्देश देने की मांग करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की। याचिका को माननीय उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया। अपीलकर्ताओं की लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज करते हुए माननीय उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने निर्णय को बरकरार रखा।

इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह था कि क्या बोर्ड की ओर से - संविदात्मक या वैधानिक, या न्यायसंगत विचारों पर - अपीलकर्ताओं की सेवाओं को अवशोषित करने का कोई दायित्व था?

अपीलकर्ताओं ने अन्य बातों के *साथ-साथ* **तर्क दिया कि उनकी वैध अपेक्षा थी, इस तथ्य के मद्देनजर कि पहले, जब बोर्ड ने तत्कालीन अनुज्ञप्तिधारियों के उपक्रमों को अपने अधिकार में लिया था, तो उसने उनके कर्मचारियों की सेवाओं को भी अपने अधिकार में ले लिया था; कि**

कुछ वाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समान परिस्थितियों में अवशोषण का निर्देश दिया था।

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित: 1. बोर्ड ने न तो सोसाइटी के साथ कोई अनुबंध किया, और न ही सोसाइटी या उसके कर्मचारियों को सोसायटी के कर्मचारियों को अपनी सेवा में अवशोषित करने का कोई आश्वासन दिया। इसलिए, अपीलकर्ताओं की सेवाओं को अवशोषित करने के लिए बोर्ड की ओर से कोई संविदात्मक दायित्व नहीं है। [522-बी]

2. विद्युत अधिनियम, 1910 के किसी भी प्रावधान में उपक्रम के खरीदार को सोसाइटी के कर्मचारियों की सेवाओं को लेने की आवश्यकता नहीं थी। अपीलकर्ताओं कोई अन्य वैधानिक प्रावधान दिखाने में सक्षम नहीं हैं जो उन्हें बोर्ड द्वारा अवशोषण मांगने का हकदार बनाता हो। इसलिए, उन्हें बोर्ड की सेवा में अवशोषित करने का कोई वैधानिक दायित्व नहीं है। [522-ई]

3.1. वैध अपेक्षा कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यह एक लाभ, राहत या उपाय की अपेक्षा है, जो सामान्य रूप से किसी वादे या स्थापित प्रथा से प्रवाहित हो सकती है। शब्द 'स्थापित प्रथा' निर्णय लेने वाले प्राधिकरण के नियमित, सुसंगत, अनुमानित और निश्चित आचरण, प्रक्रिया या गतिविधि को संदर्भित करता है। अपेक्षा वैध होनी चाहिए, अर्थात, उचित, तार्किक और मान्य। कोई भी अपेक्षा जो छिटपुट या आकस्मिक या यादृच्छिक कार्यों पर आधारित है, या जो अनुचित, अतार्किक या अमान्य है, वह वैध अपेक्षा नहीं हो सकती है। अधिकार न होने के कारण, यह इस रूप में प्रवर्तनीय नहीं है। यह प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा के लिए

न्यायालयों द्वारा बनाई गई एक अवधारणा है। यह किए गए वादे या स्थापित प्रथा के परिणामस्वरूप प्रशासनिक कार्रवाई में उच्च स्तर की निष्पक्षता की आवश्यकता पर आधारित प्रकृति में प्रक्रियात्मक है। राहत के आधार के रूप में, सिद्धांत की प्रभावकारिता बल्कि कमजोर है क्योंकि इसका स्थान 'कार्रवाई में निष्पक्षता' से ठीक ऊपर है लेकिन वचन विबंध से बहुत नीचे है। यह केवल एक अपेक्षा करने वाले को हकदार बना सकता है: (ए) अपेक्षा के टूटने से पहले कारण बताओ का अवसर; या (बी) इनकार के कारण के स्पष्टीकरण के लिए। उपयुक्त वाद में, न्यायालय प्राधिकरण को वादा की गई प्रक्रिया या स्थापित प्रथा का पालन करने की आवश्यकता वाला निर्देश दे सकते हैं। एक वैध अपेक्षा, भले ही सिद्ध हो जाए, हमेशा नहीं अपेक्षा करने वाले को राहत का हकदार बनाती है। जनहित, नीति में बदलाव, अपेक्षा करने वाले का आचरण या निर्णय लेने वाले द्वारा दिया गया कोई अन्य मान्य यासद्भावनापूर्ण कारण, 'वैध अपेक्षा' को नकारात्मक करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। [523-बी-एफ]

यूनियन ऑफ इंडिया बनाम हिंदुस्तान डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, (1993) 3 एस.सी.सी. 499; *पंजाब कम्युनिकेशन लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया,* (1999) 4 एस.सी.सी. 727; *सचिव, कर्नाटक राज्य बनाम उमादेवी,* (2006) 4 एस.सी.सी. 1 *और कन्फेडरेशन ऑफ एक्स-सर्विसमेन एसोसिएशंस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया,* जे.टी. (2006) 8 एस.सी. 547 में, संदर्भित किया गया।

3.2. स्थापित प्रथा पर आधारित वैध अपेक्षा का सिद्धांत (वादे पर आधारित वैध अपेक्षा के विपरीत), केवल उसी व्यक्ति द्वारा लागू किया जा सकता है जिसका किसी प्राधिकरण के साथ व्यवहार या लेनदेन या बातचीत है, जिस पर ऐसी स्थापित प्रथा का असर होता है, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसका प्राधिकरण के साथ एक मान्यता प्राप्त विधिक संबंध है। प्राधिकरण से असंबंधित एक कुल अजनबी या एक व्यक्ति जिसका प्राधिकरण के साथ कोई पिछला व्यवहार

नहीं था और जिसने प्राधिकरण के साथ कोई लेनदेन या बातचीत नहीं की है, केवल इस आधार पर वैध अपेक्षा के सिद्धांत का आह्वान नहीं कर सकता है कि प्राधिकरण का निष्पक्ष रूप से कार्य करने का सामान्य दायित्व है।

[523-जी; 524-ए]

3.3. कई दशक पहले जब बोर्ड ने अपना संचालन शुरू किया था और जब उसकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ थी, तब जो कुछ हुआ था, उसका वर्ष 1995 में उसके कार्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। 1995 में सोसाइटी के सापेक्ष बोर्ड की स्थिति, कई दशक पहले जब बोर्ड ने कई पूर्व-अनुज्ञप्तिधारियों के उपक्रमों को अपने अधिकार में लिया था, तब उनके सापेक्ष बोर्ड की स्थिति से पूरी तरह अलग थी। यह वैध अपेक्षा के सिद्धांत को आकर्षित नहीं करता है।

[527-सी]

3.4. यह धारणा कि जब भी किसी उपक्रम को लिया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है या खरीदा जाता है, तो अंतरिती या खरीदार को उपक्रम के तत्कालीन मालिक के कर्मचारियों की सेवाओं को जारी रखना चाहिए, सही नहीं है। वास्तव में, वैधानिक प्रावधान अन्यथा संकेत देते प्रतीत होते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-एफ एफ यह प्रावधान करती है कि जहां किसी उपक्रम का स्वामित्व या प्रबंधन, चाहे समझौते द्वारा या कानून के संचालन द्वारा, उस उपक्रम के संबंध में नियोक्ता से एक नए नियोक्ता को स्थानांतरित किया जाता है, वहां प्रत्येक कर्मकार जो उस उपक्रम में ऐसे हस्तांतरण से ठीक पहले एक वर्ष से कम नहीं की निरंतर सेवा में रहा है, अधिसूचना और क्षतिपूर्ति का हकदार होगा, धारा 25-एफ के प्रावधानों के अनुसार, मानो कर्मकार की छंटनी कर दी गई हो, सिवाय इसके प्रावधान में उल्लिखित वाद के। इसलिए, एक उपक्रम के 1-1 हस्तांतरण का स्वाभाविक परिणाम, जब तक

कि कर्मकारों की सेवा जारी रखने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान न हो, उसके कर्मचारियों के रोजगार की समाप्ति है, और धारा 25-एफ के अनुसार क्षतिपूर्ति देने का नियोक्ता का दायित्व है। [527-एफ]

अनकापल्ले को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी लिमिटेड बनाम वर्कमेन, ए.आई.आर. (1963) एस.सी. 1489, का पालन किया गया।

3.5. बोर्ड ने कभी भी सोसाइटी के किसी भी कर्मचारी की सेवाएं लेने के लिए न तो सहमति दी और न ही निर्णय लिया। वास्तव में, यह अपीलकर्ताओं का वाद भी नहीं है कि बोर्ड ने किसी भी समय उनकी सेवाओं को अवशोषित करने का कोई वादा या आश्वासन दिया था। जब सोसाइटी का अनुज्ञप्ति रद्द किया गया, तो राज्य सरकार ने यह जांचने के लिए एक समिति नियुक्त की कि क्या बोर्ड सोसाइटी के कर्मचारियों की सेवाएं ले सकता है। समिति ने निस्संदेह सिफारिश की कि योग्य और अर्हता प्राप्त कर्मचारियों की सेवाएं ली जानी चाहिए। लेकिन इसके बाद राज्य सरकार ने सिफारिश पर विचार किया और इसे खारिज कर दिया, जाहिर तौर पर बोर्ड की अनिश्चित स्थिति के कारण जो स्वयं गंभीर वित्तीय संकट में था, और अपने स्वयं के कर्मचारियों की छंटनी पर विचार कर रहा था। हर हाल में, राज्य सरकार द्वारा सोसायटी के कर्मचारियों के अवशोषण की सिफारिश करने या निर्देश देने का कोई भी निर्णय बोर्ड पर बाध्यकारी नहीं था, क्योंकि यह एक ऐसा मामला था जहाँ वह स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता था। यह भी विवाद में नहीं है कि 1995 से पहले दो दशकों या उससे अधिक समय तक, बोर्ड ने किसी निजी अनुज्ञप्तिधारी के कर्मचारियों को नहीं लिया था। इस तरह के पाठ्यक्रम पर विचार करने का कोई अवसर नहीं था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि कार्रवाई में कोई नियमितता या भविष्यवाणी या निश्चितता थी जो एक वैध अपेक्षा को जन्म दे सकती है।

[528-सी-ई]

3.6. यह भी संभव है कि यह न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, किसी दिए गए वाद के तथ्यों पर, निर्देश दे सकता था कि वे व्यक्ति, जिनकी सेवाएं राज्य के एक उपक्रम के बंद होने के कारण समाप्त कर दी गई थीं, सरकारी विभागों या अन्य सरकारी निगमों की सेवा में बने रहें। अनुच्छेद 142 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए विशेष तथ्यों पर दिया गया कोई भी निर्देश, बाध्यकारी नज़ीर नहीं है। [529-ए-बी]

सचिव, कर्नाटक राज्य बनाम उमादेवी, **(2006) 4 एस.सी.सी. 1**, पर **अवलंबन**।

जी. गोविंदा राजुलु बनाम आंध्र प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, **[1986] (पूरक) एस.सी.सी. 651, में अंतर स्पष्ट किया गया।**

3.7. अपीलकर्ताओं, न्यायसंगत विचारों पर, कार्रवाई में निष्पक्षता के सिद्धांत के आधार पर राहत के हकदार नहीं हैं। इस अपील में विचारणीय प्रश्न सोसाइटी या राज्य सरकार के सापेक्ष सोसाइटी के कर्मचारियों के अधिकारों के बारे में नहीं है। यह एक विशिष्ट प्रश्न के संबंध में है कि क्या वे बोर्ड के तहत अवशोषण की मांग कर सकते हैं। बोर्ड का उपक्रम के पिछले मालिक के कर्मचारियों के प्रति कोई दायित्व नहीं है।

529-सी; 533-सी]

सचिव, कर्नाटक राज्य बनाम उमादेवी, **[2006] 4 एस.सी.सी. 1 और** *भोला नाथ मुखर्जी बनाम पश्चिम बंगाल सरकार,* **[1997] 1 एस.सी.सी. 562, पर अवलंबन**।

गुरमेल सिंह बनाम पंजाब राज्य, **[1991] 1 एस.सी.सी. 189 और** *कपिला हिंगोरानी बनाम बिहार राज्य,* **[2003] 6 एस.सी.सी. 1, में अंतर स्पष्ट किया गया।**

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2004 की दीवानी अपील संख्या 4119.

लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1030/2002 में पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में दिनांक 30.9.2002 के अंतिम आदेश से।

पी.एस. मिश्रा, गौरव अग्रवाल, उपेंद्र मिश्रा, ध्रुव कुमार झा और प्रशांत कुमार, अपीलकर्ताओं के लिए।

कैलाश वासुदेव, नवीन प्रकाश, निशाकांत पांडे, गोपाल सिंह और चंद्र शेखर अश्री , उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय

रवींद्रन, न्यायमूर्ति द्वारा दिया गया - अपीलकर्ताओं जो फतुहा फुलवारीशरीफ ग्राम्य विद्युत सहकारी समिति लिमिटेड, परिसमापन के तहत एक सहकारी समिति के कर्मचारी थे, ने पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.9.2002 को चुनौती दी है, जिसमें उनकी अपील (लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1030/2002) को खारिज कर दिया गया था, जो उनकी रिट याचिकाओं को खारिज करने वाले एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.2.2002 के विरुद्ध थी।

2. 1976 से पहले, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (संक्षेप में, 'बोर्ड') पटना के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति कर रहा था। वर्ष 1976 में, बिहार सरकार, बोर्ड और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने बिहार सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी को अस्तित्व में लाया, जिसे फतुहा - फुलवारीशरीफ ग्राम्य विद्युत सहकारी समिति लिमिटेड (संक्षेप में 'सोसाइटी') के रूप में जाना जाता है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के बेहतर वितरण के लिए एक आर.ई.सी. योजना को लागू किया जा सके। राज्य सरकार ने भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 3 के तहत सोसाइटी को फतुहा और फुलवारी शरीफ ब्लॉकों में बिजली की आपूर्ति करने के लिए, 20 वर्षों की अवधि के लिए, अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति की अवधि बढ़ाने के विकल्पों के साथ, दिनांक 24.8.1976 का अनुज्ञप्ति दिया।

3. पत्र दिनांक 23.4.1993 द्वारा, बोर्ड ने राज्य सरकार से सोसाइटी को दिए गए अनुज्ञप्ति को रद्द करने और तीन कारण बताते हुए सोसाइटी का बोर्ड के साथ विलय करने की सिफारिश की: (i) जिस उद्देश्य के लिए सोसाइटी बनाई गई थी वह अब मौजूद नहीं है। (ii) सोसाइटी बोर्ड के वितरण नेटवर्क में कई बिंदुओं से बिजली ले रही थी, जिससे सोसाइटी द्वारा ली गई बिजली की वास्तविक मात्रा का पता लगाना मुश्किल हो गया था। (iii) सोसाइटी की वित्तीय स्थिति और प्रबंधन बहुत खराब स्थिति में था और सोसाइटी पर बोर्ड का भारी बकाया था, इसके बावजूद कि बोर्ड इसे सोसाइटी को 7 पैसे प्रति यूनिट (90 से 115 पैसे प्रति यूनिट की बोर्ड की लागत मूल्य के मुकाबले) पर आपूर्ति कर रहा था।

4. राज्य सरकार ने मामले पर विचार करने के बाद, अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, दिनांक 25.4.1995 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें

सोसाइटी को दिए गए दिनांक 24.8.1976 के अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। राज्य सरकार ने सोसाइटी की उन संपत्तियों का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति का भी गठन किया जिन्हें बोर्ड को हस्तांतरित किया जाना था। समिति को यह भी विचार करना आवश्यक था कि क्या बोर्ड के लिए सोसाइटी के कुछ कर्मचारियों को अवशोषित करना उपयोगी होगा। 18.9.1995 को आयोजित एक बैठक में (10.11.1995 को तैयार किए गए कार्यवृत्त के अनुसार), उक्त समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिए:

(ए) अनुज्ञप्ति रद्द होने के मद्देनजर सोसाइटी का परिसमापन किया जाना चाहिए;

(बी) सोसायटी के परिसमापक को सोसायटी को देय राशि वसूल करनी चाहिए और दावों के निपटान के लिए सोसायटी के लेनदारों से दावे भी आमंत्रित करने चाहिए;

(सी) रद्दीकरण की तारीख (25.4.1995) तक आपूर्ति की गई बिजली के संबंध में देय राशि सोसाइटी को जमा की जानी चाहिए, और उसके बाद आपूर्ति की गई बिजली के लिए देय राशि बोर्ड द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए;

(डी) अनुज्ञप्ति रद्द करने की तारीख से सोसाइटी और बोर्ड की आय और व्यय से संबंधित खातों को अलग से रखा जाना चाहिए, ताकि वे अपने बीच खातों का निपटारा कर सकें; और

(ई) बोर्ड को सोसाइटी के कर्मचारियों से काम लेने और उन्हें वेतन देने पर विचार करना चाहिए। बोर्ड सोसाइटी के योग्य कर्मचारियों को यह जांचने के बाद

अवशोषित करने पर भी विचार कर सकता है कि क्या वे पदों के लिए योग्य थे और विधिवत नियुक्त किए गए थे और क्या उनका वेतन-निर्धारण ठीक से किया गया है।

5. राज्य सरकार ने पत्र दिनांक 2.1.1996 द्वारा बोर्ड से अनुरोध किया कि वह समिति के उस सुझाव को लागू करे जो सोसाइटी के कर्मचारियों से संबंधित था कि बोर्ड को सोसाइटी के कर्मचारियों से काम लेना चाहिए और उनका वेतन देना चाहिए, और पात्र कर्मचारियों के अवशोषण पर भी विचार करना चाहिए। 1996 में विधानमंडल के पटल पर कुछ आश्वासन भी दिया गया था कि बोर्ड को सोसाइटी के उपक्रम को उसके कर्मचारियों के साथ लेने के लिए राजी किया जाएगा। हालांकि, इसके बाद, राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि सोसाइटी की संपत्ति और देनदारियों को बोर्ड को हस्तांतरित किया जाना चाहिए, लेकिन सोसाइटी के कर्मचारियों की सेवाओं को नहीं। उक्त निर्णय ऊर्जा विभाग के सचिव द्वारा सहकारी विभाग के सचिव और बोर्ड को पत्र दिनांक 24.2.1997 द्वारा सूचित किया गया था।

6. बोर्ड द्वारा सोसाइटी के कर्मचारियों की सेवाओं के अवशोषण के प्रस्ताव को खारिज किए जाने के मद्देनजर, सोसाइटी के प्रशासक द्वारा कर्मचारियों की सेवाओं को अवशोषित करने के लिए राज्य सरकार को कई अभ्यावेदन भेजे गए थे। सोसाइटी के प्रशासक ने राज्य सरकार को पदनामों और शैक्षिक तथा तकनीकी योग्यताओं के विवरण के साथ सोसाइटी के कर्मचारियों की एक सूची भी प्रस्तुत की। कर्मचारियों की संख्या 225 है जो इंजीनियरों से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तक है। उक्त सूची राज्य सरकार द्वारा 14.7.1999 को बोर्ड को इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी कि बोर्ड में मौजूदा रिक्तियों का पता लगाया जाए। बोर्ड द्वारा सोसाइटी के

उपयुक्त और फिट कर्मचारियों के अवशोषण के लिए विभिन्न हलकों से सुझावों से संबंधित कुछ और पत्राचार भी हुए थे।

7. लेकिन बोर्ड ने सोसाइटी के कर्मचारियों की सेवाओं को अवशोषित नहीं किया। इसलिए, सोसाइटी के कर्मचारियों (अपीलकर्ताओं) ने बोर्ड को उन्हें सेवा की निरंतरता के साथ समकक्ष पदों पर अवशोषित करने और उनके वेतन, भत्ते और अन्य बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश देने की मांग करते हुए सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 1503/2000 और 14394/2001 दायर की। उन्होंने तर्क दिया कि उनके पास कानून और न्याय व्यवस्था दोनों में अधिकार था, और साथ ही बोर्ड की सेवाओं में अवशोषित होने की 'वैध अपेक्षा' भी थी, जिसके निम्नलिखित कारण थे:

(ए) राज्य सरकार द्वारा गठित समिति ने सिफारिश की थी कि बोर्ड को सोसायटी के कर्मचारियों से काम लेना चाहिए और अंततः उन्हें अवशोषित करना चाहिए;

(बी) सोसायटी के कर्मचारियों की 'वैध अपेक्षा' है कि उन्हें बोर्ड द्वारा निम्नलिखित कारणों से अवशोषित किया जाना चाहिए:

(i) शुरू में कई निजी कंपनियां राज्य में बिजली पैदा कर रही थीं और वितरित कर रही थीं। जब बोर्ड का गठन किया गया, तो उन सभी निजी कंपनियों के उपक्रमों को अपने अधिकार में ले लिया गया और उनके सभी कर्मचारियों को बोर्ड की सेवाओं में अवशोषित कर लिया गया।

(ii) जब भी किसी कंपनी या संस्थान का उपक्रम किसी वैधानिक निकाय या निगम द्वारा लिया गया, तो ऐसे उपक्रम के कर्मचारियों की सेवाएं भी सामान्य रूप से ले ली जाती हैं।

(iii) जब कोई 'उपक्रम' खरीदा जाता है, तो इसके विपरीत किसी इरादे के अभाव में, सभी संपत्ति और देनदारियां, और साथ ही सभी कर्मचारियों की सेवाएं खरीदार को हस्तांतरित कर दी जाती हैं और इसलिए बोर्ड उन्हें अवशोषित करने से इनकार नहीं कर सकता।

(iv) जब बिहार राज्य द्वारा कुछ विभागों को समाप्त कर दिया गया था, तो इस माननीय न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय ने छंटनी किए गए कर्मचारियों को राज्य सरकार के अन्य विभागों में अवशोषण का निर्देश देते हुए कई आदेश पारित किए थे।

(v) सोसाइटी का गठन बोर्ड और राज्य सरकार द्वारा उन कार्यों का निर्वहन करने के लिए किया गया था जो पहले बोर्ड द्वारा किए जा रहे थे। बिजली वितरित करने के लिए सोसायटी को दिया गया अनुज्ञप्ति बाद में बोर्ड की सिफारिश पर रद्द कर दिया गया था। बोर्ड ने सोसायटी के उपक्रम को लेने की अपनी तत्परता व्यक्त की है। बोर्ड ने वास्तव में सोसाइटी की संपत्तियों को अपने अधिकार में ले लिया है और 25.4.1995 को सोसाइटी का अनुज्ञप्ति रद्द होने पर बिना किसी रुकावट के सोसाइटी के कार्यों का निर्वहन कर रहा है।

(vi) बोर्ड ने 25.4.1995 से मई, 1996 तक सोसायटी के कर्मचारियों से कुछ काम लिया था।

(सी) विभिन्न श्रेणियों के पदों पर बोर्ड में बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं और बोर्ड द्वारा उनकी सेवाओं के अवशोषण में कोई कठिनाई नहीं होगी।

(डी) सोसाइटी के सभी कर्मचारियों ने नई नौकरी पाने के लिए अधिकतम आयु सीमा पार कर ली है और यदि उन्हें बोर्ड द्वारा अवशोषित नहीं किया गया, तो वे अपनी आजीविका से वंचित हो जाएंगे।

(ई) सोसाइटी राज्य सरकार और बोर्ड की एक अंग थी, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर 'राज्य' की परिभाषा का उत्तर देती थी। जब राज्य के ऐसे अंग के उपक्रमों को राज्य के किसी अन्य अंग द्वारा लिया जाता है, तो 'कार्रवाई में निष्पक्षता', जो एक 'राज्य' की पहचान में से एक है, यह अपेक्षा करती है कि उचित तरीके से उनके अवशोषण का प्रावधान करके कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा की जाए।

राज्य सरकार ने अपने प्रति-शपथपत्र में, रिट याचिकाकर्ताओं के दावे से इनकार करते हुए, हालांकि यह स्वीकार किया कि अगस्त, 2001 में, उसने एक निर्णय लिया था कि जब बोर्ड में भर्ती पर रोक हटा दी जाएगी और भविष्य में नियुक्तियां की जाएंगी, तो यदि आवश्यक हो तो आयु सीमा में छूट देकर सोसाइटी के पात्र कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

8. माननीय उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त तर्कों को खारिज कर दिया और परिणामतः, आदेश दिनांक 24.2.2002 द्वारा रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। उन्होंने अभिनिर्धारित किया:

(i) राज्य सरकार ने बोर्ड को सोसाइटी के कर्मचारियों की सेवाओं को अवशोषित करने का कोई विशिष्ट निर्देश नहीं दिया था। राज्य सरकार द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय कि जब भर्ती पर रोक हटाई जाएगी और नियुक्तियां की जाएंगी, तो बोर्ड को सोसाइटी के पात्र कर्मचारियों को प्राथमिकता देनी चाहिए, अपने आप में बोर्ड को कोई निर्देश नहीं था। हर हाल में, विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 78ए को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार केवल नीतिगत मामलों के संबंध में निर्देश जारी कर सकती है, लेकिन अपनी सेवा में सोसाइटी के किसी भी कर्मचारी को नियुक्त करने या अवशोषित करने का निर्देश जारी नहीं कर सकती क्योंकि यह अधिनियम की धारा 15 के तहत बोर्ड की शक्ति का अतिक्रमण होगा - देखें *राकेश रंजन वर्मा बनाम बिहार राज्य,* [1992] (पूरक) 2 एस.सी.सी. 343.

(ii) भले ही सोसाइटी को राज्य का एक अंग माना जाता, तो भी यह अपीलकर्ताओं को यह तर्क देने में सहायता नहीं करेगा कि सोसाइटी बोर्ड का विस्तार थी, न ही बोर्ड पर सोसायटी के कर्मचारियों को अवशोषित करने का कोई दायित्व डालती है। जब अधिनियम की धारा 3 के तहत दिया गया अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया गया था और सोसाइटी (अनुज्ञप्तिधारी) के उपक्रम को बोर्ड द्वारा खरीदे जाने की सहमति दी गई थी, तो अधिनियम के प्रावधान मामले को नियंत्रित करते थे और उन प्रावधानों ने अपीलकर्ताओं

को बोर्ड की सेवाओं में अवशोषित होने के किसी भी अधिकार का दावा करने में सक्षम नहीं बनाया।

(iii) यह तथ्य कि बोर्ड ने उन निजी कंपनियों के उपक्रमों को अपने अधिकार में ले लिया जो तब तक बिजली पैदा कर रही थीं और वितरित कर रही थीं, ऐसे निजी उपक्रमों के कर्मचारियों की सेवाओं के साथ, अपीलकर्ताओं के अवशोषण के दावे से कोई प्रासंगिकता नहीं थी। तत्कालीन अनुज्ञप्तिधारियों के उपक्रम और कर्मचारियों की सेवाएं कई दशक पहले ली गई थीं जब बोर्ड का गठन किया गया था और जब बोर्ड वित्तीय और प्रशासनिक रूप से पूरी तरह से अलग स्थिति में था। चूंकि विभिन्न परिस्थितियों, विशेष रूप से बिहार राज्य के पुनर्गठन के बाद झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना के कारण बोर्ड की वित्तीय स्थिति वर्तमान में अनिश्चित थी और चूंकि बोर्ड स्वयं अपने मौजूदा कर्मचारियों की बड़ी संख्या में छंटनी पर विचार कर रहा था, इसलिए अपीलकर्ताओं में किसी भी कानूनी अधिकार के अभाव में सोसायटी के कर्मचारियों की सेवाएं लेने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है।

(iv) यह न्यायसंगत आधार पर अवशोषण का निर्देश नहीं दे सका। अपीलकर्ताओं के दावे का कोई भी न्यायसंगत विचार बोर्ड की वित्तीय स्थिति की अनदेखी नहीं कर सकता है, चाहे न्यायालय अपीलकर्ताओं की दुर्दशा को कितनी भी सहानुभूतिपूर्वक क्यों न देखे। राज्य सरकार ने सोसाइटी के कर्मचारियों के कल्याण में रुचि रखते हुए सोसाइटी के कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए कई विकल्पों पर विचार किया था। विभिन्न विकल्पों की खोज के दौरान, सरकार द्वारा जानकारी मांगी गई थी, विचार व्यक्त किए गए थे और सदन के पटल पर आश्वासन दिए गए थे, ताकि बोर्ड द्वारा सोसाइटी के कर्मचारियों की

सेवाओं को अवशोषित करने की संभावना तलाशी जा सके। लेकिन इससे सोसाइटी के कर्मचारियों को बोर्ड से रोजगार मांगने का कोई अधिकार नहीं मिल गया। अपीलकर्ताओं की सेवाओं को अवशोषित करने के लिए बोर्ड द्वारा किसी विशिष्ट निर्णय या बोर्ड द्वारा आश्वासन के अभाव में, 'वैध अपेक्षा' का सिद्धांत आकर्षित नहीं हुआ।

(v) अधिनियम की धारा *7* और *7* ए को ध्यान में रखते हुए, जब किसी अनुज्ञप्तिधारी का उपक्रम बोर्ड द्वारा खरीदा गया था, तो बोर्ड की ओर से तत्कालीन अनुज्ञप्तिधारी के कर्मचारियों को अवशोषित करने का कोई दायित्व नहीं था।

9. विद्वान एकल न्यायाधीश के उक्त निर्णय के विरुद्ध अपीलकर्ताओं द्वारा दायर लेटर्स पेटेंट अपील को खंड पीठ ने एक संक्षिप्त आदेश दिनांक 30.9.2002 द्वारा परिसीमा और गुण-दोष दोनों आधारों पर खारिज कर दिया, जिससे विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय की पुष्टि हुई। इस अपील में उक्त आदेश को चुनौती दी गई है। दिए गए तर्कों पर, हमारे विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न उठता है:-

क्या बोर्ड की ओर से - संविदात्मक या वैधानिक, या न्यायसंगत विचारों पर - अपीलकर्ताओं की सेवाओं को अवशोषित करने का कोई दायित्व है?

संविदात्मक दायित्व:

10. भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 3 के तहत सोसाइटी को दिया गया अनुज्ञप्ति राज्य सरकार द्वारा 25.4.1995 को रद्द कर दिया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि

इस तरह के रद्दीकरण पर, बोर्ड ने अनुज्ञप्ति प्राप्त क्षेत्रों में बिजली वितरण से संबंधित सोसाइटी की पूरी गतिविधियों को अपने अधिकार में ले लिया। बोर्ड ने सोसाइटी के उपक्रम को खरीदने के लिए अपनी सहमति भी दी। लेकिन बोर्ड ने न तो सोसाइटी के साथ कोई अनुबंध किया, और न ही सोसाइटी या उसके कर्मचारियों को सोसाइटी के कर्मचारियों को अपनी सेवा में अवशोषित करने का कोई आश्वासन दिया। इसलिए, स्पष्ट रूप से, अपीलकर्ताओं की सेवाओं को अवशोषित करने के लिए बोर्ड की ओर से कोई संविदात्मक दायित्व नहीं है।

वैधानिक दायित्व:

11. अधिनियम की धारा 3 किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किसी व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञप्ति देने से संबंधित है। धारा 4 ऐसे अनुज्ञप्ति के रद्दीकरण से संबंधित है। अनुज्ञप्ति रद्द होने पर प्रभावी होने वाले प्रावधानों को धारा 5 में सूचीबद्ध किया गया था। धारा 6 ने विद्युत बोर्ड और राज्य सरकार को उसमें उल्लिखित परिस्थितियों में अनुज्ञप्तिधारी के उपक्रम को खरीदने का विकल्प दिया। धारा 7 में धारा 5 या 6 के तहत खरीदार को बेचे गए अनुज्ञप्तिधारी के उपक्रम के निहित होने का प्रावधान है। धारा 7ए ने खरीद मूल्य के निर्धारण का प्रावधान किया। अधिनियम के इन प्रावधानों में से किसी में भी उपक्रम के खरीदार को सोसाइटी के कर्मचारियों की सेवाएं लेने की आवश्यकता नहीं थी। अपीलकर्तागण कोई अन्य वैधानिक प्रावधान दिखाने में सक्षम नहीं हैं जो उन्हें बोर्ड द्वारा अवशोषण मांगने का हकदार बनाता हो। इसलिए, उन्हें बोर्ड की सेवा में अवशोषित करने का कोई वैधानिक दायित्व नहीं है।

न्यायसंगत विचार:

12. यह महसूस करते हुए कि अपीलकर्ताओं के पास कोई संविदात्मक या वैधानिक अधिकार नहीं है, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दिए गए तर्कों को दोहराते हुए, वैध अपेक्षा, कार्रवाई में निष्पक्षता और नैसर्गिक न्याय से संबंधित सिद्धांतों के मिश्रण पर भरोसा करके न्यायसंगत विचारों पर दावे के लिए समर्थन प्राप्त करने की मांग की।

13. यह सच हो सकता है कि जब बोर्ड ने कई दशक पहले तत्कालीन निजी अनुज्ञप्तिधारियों के उपक्रमों को अपने अधिकार में लिया था, तो उसने ऐसे निजी अनुज्ञप्तिधारियों के कर्मचारियों की सेवाओं को भी अपने अधिकार में ले लिया था। यह भी संभव है कि यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, किसी दिए गए वाद के तथ्यों पर, यह निर्देश दे सकता था कि वे व्यक्ति, जिनकी सेवाएं राज्य के एक उपक्रम के बंद होने के कारण समाप्त कर दी गई थीं, सरकारी विभागों या अन्य सरकारी निगमों की सेवा में बने रहें। यह भी सच हो सकता है कि राष्ट्रीयकरण या अन्यथा के अनुसरण में उपक्रमों के हस्तांतरण के लिए प्रावधान करने वाले कुछ अधिनियमों ने भी उपक्रमों के कर्मचारियों की सेवाओं को अंतरिती को जारी रखने/हस्तांतरित करने का प्रावधान किया था। लेकिन ये 'वैध अपेक्षा' के सिद्धांत को आकर्षित नहीं करते हैं।

14. वैध अपेक्षा क्या है? जाहिर है, यह कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यह एक लाभ, राहत या उपाय की अपेक्षा है, जो सामान्य रूप से किसी वादे या स्थापित प्रथा से प्रवाहित हो सकती है। शब्द 'स्थापित प्रथा' निर्णय लेने वाले प्राधिकरण के नियमित, सुसंगत, अनुमानित और निश्चित आचरण, प्रक्रिया या गतिविधि को संदर्भित करता है। अपेक्षा वैध होनी चाहिए, अर्थात, उचित, तार्किक और मान्य। कोई भी अपेक्षा जो छिटपुट या आकस्मिक या यादृच्छिक

कार्यों पर आधारित है, या जो अनुचित, अतार्किक या अमान्य है, वह वैध अपेक्षा नहीं हो सकती है। अधिकार न होने के कारण, यह इस रूप में प्रवर्तनीय नहीं है। यह प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा के लिए न्यायालयों द्वारा बनाई गई एक अवधारणा है। यह किए गए वादे, या स्थापित प्रथा के परिणामस्वरूप प्रशासनिक कार्रवाई में उच्च स्तर की निष्पक्षता की आवश्यकता पर आधारित प्रकृति में प्रक्रियात्मक है। संक्षेप में, किसी व्यक्ति को किसी विशेष उपचार की 'वैध अपेक्षा' कहा जा सकता है, यदि किसी प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट रूप से या विवक्षित रूप से कोई अभ्यावेदन या वादा किया जाता है, या यदि प्राधिकरण का नियमित और सुसंगत पिछला अभ्यास सामान्य पाठ्यक्रम में ऐसी अपेक्षा के लिए जगह देता है। राहत के आधार के रूप में, सिद्धांत की प्रभावकारिता बल्कि कमजोर है क्योंकि इसका स्थान 'कार्रवाई में निष्पक्षता' से ठीक ऊपर है लेकिन 'वचन विबंध' से बहुत नीचे है। यह केवल एक अपेक्षा करने वाले को हकदार बना सकता है: (ए) अपेक्षा के टूटने से पहले कारण बताओ का अवसर; या (बी) इनकार के कारण के स्पष्टीकरण के लिए। उपयुक्त वाद में, न्यायालय प्राधिकरण को वादा की गई प्रक्रिया या स्थापित प्रथा का पालन करने की आवश्यकता वाला निर्देश दे सकते हैं। एक वैध अपेक्षा, भले ही सिद्ध हो जाए, हमेशा अपेक्षा करने वाले को राहत का हकदार नहीं बनाती है। जनहित, नीति में बदलाव, अपेक्षा करने वाले का आचरण या निर्णय लेने वाले द्वारा दिया गया कोई अन्य मान्य या *सद्भावनापूर्ण* कारण, 'वैध अपेक्षा' को नकारात्मक करने के लिए पर्याप्त हो सकता है।

स्थापित प्रथा पर आधारित वैध अपेक्षा का सिद्धांत (वादे पर आधारित वैध अपेक्षा के विपरीत), केवल उसी व्यक्ति द्वारा लागू किया जा सकता है जिसका किसी प्राधिकरण के साथ व्यवहार या लेनदेन या बातचीत है, जिस पर ऐसी स्थापित प्रथा का असर होता है, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसका प्राधिकरण के साथ एक मान्यता प्राप्त विधिक संबंध है। प्राधिकरण से

असंबंधित एक पूर्ण अजनबी या एक व्यक्ति जिसका प्राधिकरण के साथ कोई पिछला व्यवहार नहीं था और जिसने प्राधिकरण के साथ कोई लेनदेन या बातचीत नहीं की है, केवल इस आधार पर वैध अपेक्षा के सिद्धांत का आह्वान नहीं कर सकता है कि प्राधिकरण का निष्पक्ष रूप से कार्य करने का सामान्य दायित्व है।

15. *यूनियन ऑफ इंडिया बनाम (हिंदुस्तान डेवलपमेंट) कॉरपोरेशन*, [1993] 3 एस.सी.सी. 499, में इस न्यायालय ने 'वैध अपेक्षा' के सिद्धांत की प्रकृति और दायरे को इस प्रकार समझाया:

> "विधिक उद्देश्यों के लिए, अपेक्षा प्रत्याशा के समान नहीं हो सकती है। यह एक इच्छा, एक अभिलाषा या एक आशा से अलग है और न ही यह एक अधिकार के आधार पर दावे या मांग के बराबर हो सकती है। चाहे कोई इच्छा, अभिलाषा या आशा कितनी भी गंभीर और ईमानदार क्यों न हो और कोई भी उनके पूरा होने के प्रति कितना भी आश्वस्त क्यों न हो, वे अपने आप में एक मुखर अपेक्षा के बराबर नहीं हो सकते हैं और केवल निराशा कानूनी परिणामों को आकर्षित नहीं करती है। *यहां तक कि एक नैतिक दायित्व की ओर ले जाने वाली एक पवित्र आशा भी एक वैध अपेक्षा के बराबर नहीं हो सकती है। एक अपेक्षा की वैधता का अनुमान तभी लगाया जा सकता है जब वह कानून या रिवाज या नियमित और प्राकृतिक अनुक्रम में पालन की जाने वाली एक स्थापित प्रक्रिया की मंजूरी पर आधारित हो। फिर से यह एक वास्तविक अपेक्षा से अलग है। ऐसी अपेक्षा उचित रूप से वैध और संरक्षण योग्य होनी चाहिए। हर ऐसी वैध अपेक्षा अपने आप में एक अधिकार में फलित नहीं होती है और इसलिए यह पारंपरिक अर्थों में एक अधिकार के बराबर नहीं है।"*

[जोर दिया गया]

इस न्यायालय ने वैध अपेक्षा के सिद्धांत को लागू करके मिलने वाले उपायों को भी समझाया:

"...आम तौर पर यह सहमति है कि वैध अपेक्षा आवेदक को न्यायिक समीक्षा के लिए पर्याप्त *सुने जाने का अधिकार* देती है और वैध अपेक्षा के सिद्धांत को ज्यादातर निर्णय लेने से पहले निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार तक ही सीमित रखा जाना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप किसी वादे को नकारा जाता है या किसी उपक्रम को वापस ले लिया जाता है। सिद्धांत प्रशासनिक अधिकारियों से सीधे राहत का दावा करने की गुंजाइश नहीं देता है क्योंकि इसमें कोई भी निश्चित अधिकार शामिल नहीं है। ऐसी वैध अपेक्षा का संरक्षण अपेक्षा की पूर्ति की आवश्यकता नहीं रखता है जहां एक अधिभावी जनहित अन्यथा आवश्यक हो। दूसरे शब्दों में जहां किसी विशेष निर्णय को लेने से किसी व्यक्ति की वैध अपेक्षा पूरी नहीं होती है तो निर्णय लेने वाले को कुछ अधिभावी जनहित दिखाकर ऐसी अपेक्षा के इनकार को सही ठहराना चाहिए। इसलिए भले ही ऐसी अपेक्षा के मूल संरक्षण पर विचार किया जाता है, यह किसी विशेष व्यक्ति को पूर्ण अधिकार प्रदान नहीं करता है। यह केवल उन परिस्थितियों को सुनिश्चित करता है जिनमें उस अपेक्षा को अस्वीकार या प्रतिबंधित किया जा सकता है। *वैध अपेक्षा का वाद तब उठेगा जब कोई निकाय अभ्यावेदन द्वारा या पिछले अभ्यास द्वारा ऐसी अपेक्षा जगाता है जिसे पूरा करना उसकी शक्तियों के भीतर होगा।* संरक्षण उस सीमा तक सीमित है और न्यायिक समीक्षा उन सीमाओं के भीतर हो सकती है। लेकिन जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, एक व्यक्ति जो वैध अपेक्षा के सिद्धांत पर अपना दावा आधार बनाता है, उसे पहली बार में, यह संतुष्ट

करना होगा कि एक आधार है और इस प्रकार ऐसा दावा करने के लिए उसके पास *सुने जाने का अधिकार* है। उसी पर विचार करते हुए कई कारक जो ऐसी वैध अपेक्षा को जन्म देते हैं, मौजूद होने चाहिए। प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय मनमाना, अनुचित और जनहित में नहीं लिया गया पाया जाना चाहिए। यदि यह नीति का प्रश्न है, भले ही पुरानी नीति में बदलाव के माध्यम से हो, तो न्यायालय किसी निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। किसी दिए गए वाद में क्या ऐसे तथ्य और परिस्थितियां हैं जो वैध अपेक्षा को जन्म देती हैं, यह मुख्य रूप से तथ्य का प्रश्न होगा। यदि ये परीक्षण संतुष्ट होते हैं और यदि न्यायालय संतुष्ट है कि वैध अपेक्षा का वाद बनता है तो अगला प्रश्न यह होगा कि क्या ऐसी वैध अपेक्षा को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने से पहले सुनवाई का अवसर न देने से न्याय की असफलता हुई है और क्या उस आधार पर निर्णय को रद्द कर दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा है तो राहत क्या होनी चाहिए यह फिर से एक मामला है जो कई कारकों पर निर्भर करता है।" (जोर दिया गया)।

16. *पंजाब कम्युनिकेशन लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया,* [1999] 4 एस.सी.सी. 727 में, इस माननीय न्यायालय ने देखा:

"वैध अपेक्षा का सिद्धांत अभी भी विकास के चरण में है। सिद्धांत विधि के शासन की जड़ में है और जनता के साथ सरकार के व्यवहार में नियमितता, भविष्यवाणी और निश्चितता की आवश्यकता है.... इसका प्रक्रियात्मक हिस्सा इस अभ्यावेदन से संबंधित है कि निर्णय लेने से पहले सुनवाई या अन्य उपयुक्त प्रक्रिया प्रदान की जाएगी।"

"हालांकि, अधिक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि क्या निर्णय लेने वाला *वेडनसबरी* सिद्धांत का सहारा लेकर नीति में बदलाव को बनाए रख सकता है या क्या न्यायालय इस प्रश्न में जा सकता है कि क्या निर्णय लेने वाले ने बदलाव की आवश्यकता के विरुद्ध वैध अपेक्षा को उचित रूप से संतुलित किया है..... संक्षेप में, इसका मतलब यह है कि यह निर्णय कि क्या जनहित व्यक्तियों की मूल वैध अपेक्षा पर हावी है, उस निर्णय लेने वाले के लिए होगा जिसने नीति में बदलाव किया है। नीति का चुनाव निर्णय लेने वाले के लिए है न कि न्यायालय के लिए। वैध मूल अपेक्षा केवल न्यायालय को यह पता लगाने की अनुमति देती है कि क्या नीति में बदलाव जो वैध अपेक्षा को हराने का कारण है, तर्कहीन या विकृत है या ऐसा है जिसे कोई भी उचित व्यक्ति नहीं बना सकता था:"

17. हाल ही में, इस न्यायालय की एक संवैधान पीठ ने *सचिव, कर्नाटक राज्य बनाम उमादेवी,* [2006] 4 एस.सी.सी. 1 में उन परिस्थितियों को संदर्भित किया जिनमें वैध अपेक्षा के सिद्धांत का आह्वान किया जा सकता है, इस प्रकार:

"इस सिद्धांत का आह्वान किया जा सकता है यदि प्रशासनिक प्राधिकारी के निर्णय उस व्यक्ति को किसी ऐसे लाभ या फायदे से वंचित करके प्रभावित करते हैं जिसका (i) उसे अतीत में निर्णय लेने वाले द्वारा आनंद लेने की अनुमति दी गई थी और जिसके लिए वह वैध रूप से अपेक्षा कर सकता है कि उसे तब तक जारी रखने की अनुमति दी जाएगी जब तक कि उसे वापस लेने के लिए कुछ तर्कसंगत आधार सूचित नहीं किए जाते, जिन पर उसे टिप्पणी करने का अवसर दिया गया हो: या (ii) उसे निर्णय लेने वाले से आश्वासन मिला हो कि उन्हें वापस नहीं लिया जाएगा जब तक कि उसे पहले यह तर्क

देने के लिए कारण बताने का अवसर न दिया जाए कि उन्हें वापस क्यों नहीं लिया जाना चाहिए।"

एक अन्य संवैधान पीठ ने, इस सिद्धांत का जिक्र करते हुए, *कन्फेडरेशन ऑफ एक्स-सर्विसमेन एसोसिएशंस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया,* जे.टी. (2006) 8 एस.सी. 547 में इस प्रकार देखा:

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रशासनिक विधि और विशेष रूप से 'न्यायिक समीक्षा' से संबंधित कानून के विकास में इस सिद्धांत का महत्वपूर्ण स्थान है। उक्त सिद्धांत के तहत, एक व्यक्ति को प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा एक निश्चित तरीके से व्यवहार किए जाने की उचित या वैध अपेक्षा हो सकती है, भले ही उसे लाभ प्राप्त करने का कानून में कोई अधिकार न हो। ऐसी स्थिति में, यदि प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है जो उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तो लाभ की निरंतर प्राप्ति, लाभ या विशेषाधिकार प्राप्त करने की वैध अपेक्षा, जिसका उसने पूरे समय आनंद लिया है, के तथ्य के आलोक में उसे उचित शिकायत हो सकती है। ऐसी अपेक्षा या तो स्पष्ट वादे से या लगातार प्रथा से उत्पन्न हो सकती है जिसके जारी रहने की आवेदक उचित रूप से अपेक्षा कर सकता है।"

"ऐसे वाद में, इसलिए, न्यायालय प्रशासनिक प्राधिकारी को न्यायिक रूप से कार्य करने के लिए जोर नहीं दे सकता है लेकिन फिर भी उसे निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए जोर दे सकता है। यह सिद्धांत इस नियम पर आधारित है कि अच्छा प्रशासन तर्कसंगतता के पालन की मांग करता है और जहां उसने कानून के प्रावधान के अभाव में भी लंबे

समय तक एक विशेष प्रथा को अपनाया है, उसे अपने नागरिकों को प्राप्त लाभ या प्रयोग किए गए विशेषाधिकार से वंचित किए बिना ऐसी प्रथा का पालन करना चाहिए।"

18. अब हम जांच करते हैं कि क्या वैध अपेक्षा के सिद्धांत इस वाद में लागू हो सकते हैं। कई दशक पहले क्या घटित हुआ जब बोर्ड ने अपना परिचालन शुरू किया और जब इसकी वित्तीय स्थिति अच्छी थी, इसका वर्ष 1995 में इसकी कार्रवाई पर कोई असर नहीं हो सकता है। 1995 में सोसाइटी के सापेक्ष बोर्ड की स्थिति, कई दशक पहले जब बोर्ड ने कई पूर्व-अनुज्ञप्तिधारियों के उपक्रमों को अपने अधिकार में लिया था, तब उनके सापेक्ष बोर्ड की स्थिति से पूरी तरह अलग थी। इसके अलावा, यह धारणा कि जब भी कोई उपक्रम लिया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है या खरीदा जाता है, तो अंतरिती या खरीदार को उपक्रम के तत्कालीन मालिक के कर्मचारियों की सेवाओं को जारी रखना चाहिए, सही नहीं है। वास्तव में, वैधानिक प्रावधान अन्यथा संकेत देते प्रतीत होते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-एफ एफ यह प्रावधान करती है कि जहां किसी उपक्रम का स्वामित्व या प्रबंधन, चाहे समझौते द्वारा या कानून के संचालन द्वारा, उस उपक्रम के संबंध में नियोक्ता से एक नए नियोक्ता को स्थानांतरित किया जाता है, वहां प्रत्येक कर्मकार जो उस उपक्रम में ऐसे हस्तांतरण से ठीक पहले एक वर्ष से कम नहीं की निरंतर सेवा में रहा है, अधिसूचना और क्षतिपूर्ति का हकदार होगा, धारा 25-एफ के प्रावधानों के अनुसार, मानो कर्मकार की छंटनी कर दी गई हो, सिवाय इसके प्रावधान में उल्लिखित वाद के। इसलिए, एक उपक्रम के हस्तांतरण का स्वाभाविक परिणाम, जब तक कि कर्मकारों की सेवा जारी रखने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान न हो, उसके कर्मचारियों के रोजगार की समाप्ति है, और धारा 25-एफ के अनुसार क्षतिपूर्ति देने का नियोक्ता का दायित्व है। *अनकापल्ले को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी लिमिटेड बनाम*

वर्कमेन, ए.आई.आर. (1963) एस.सी. 1489 में, इस न्यायालय की एक संवैधान पीठ ने कर्मचारियों के इस तर्क को खारिज कर दिया कि उपक्रम के हस्तांतरण पर, उपक्रम के कर्मचारियों को उपक्रम के खरीदार/अंतरिती द्वारा अवशोषित किया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

> "क्षतिपूर्ति के भुगतान और तत्काल पुन: रोजगार के रूप में यह दोहरा लाभ निष्पक्ष खेल या न्याय के किसी भी विचार पर आधारित नहीं कहा जा सकता है। निष्पक्ष खेल और न्याय का स्पष्ट अर्थ है दोनों पक्षों के लिए निष्पक्ष खेल और सामाजिक न्याय। हमें लगता है कि यह उचित नहीं होगा कि विक्रेता अपने कर्मचारियों को इस आधार पर क्षतिपूर्ति दे कि हस्तांतरण उनकी सेवाओं की समाप्ति लाता है, और खरीदार को उन्हें वापस लेने के लिए कहा जाए इस आधार पर कि सामाजिक न्याय के सिद्धांत उसे ऐसा करने की आवश्यकता रखते हैं... और उस अर्थ में, उक्त क्षतिपूर्ति उपदान से अलग है। इसलिए, यदि हस्तांतरणकर्ता को क़ानून द्वारा अपने कर्मकारों को छंटनी का क्षतिपूर्ति देने की आवश्यकता है, तो यह सुझाव देना विसंगतिपूर्ण होगा कि जिन कर्मकारों को क्षतिपूर्ति मिला है, वे अंतरिती के हाथों प्रतिष्ठान में तत्काल पुन: रोजगार का दावा करने के हकदार हैं।"

19. बोर्ड ने कभी भी सोसाइटी के किसी भी कर्मचारी की सेवाएं लेने के लिए न तो सहमति दी और न ही निर्णय लिया। वास्तव में, यह अपीलकर्ताओं का वाद भी नहीं है कि बोर्ड ने किसी भी समय उनकी सेवाओं को अवशोषित करने का कोई वादा या आश्वासन दिया था। जब सोसाइटी का अनुज्ञप्ति रद्द किया गया, तो राज्य सरकार ने यह जांचने के लिए एक समिति नियुक्त की कि क्या बोर्ड सोसाइटी के कर्मचारियों की सेवाएं ले सकता है। समिति ने निस्संदेह

सिफारिश की कि योग्य और अर्हता प्राप्त कर्मचारियों की सेवाएं ली जानी चाहिए। लेकिन इसके बाद राज्य सरकार ने सिफारिश पर विचार किया और इसे खारिज कर दिया, जाहिर तौर पर बोर्ड की अनिश्चित स्थिति के कारण जो स्वयं गंभीर वित्तीय संकट में था, और अपने स्वयं के कर्मचारियों की छंटनी पर विचार कर रहा था। हर हाल में, राज्य सरकार द्वारा सोसायटी के कर्मचारियों के अवशोषण की सिफारिश करने या निर्देश देने का कोई भी निर्णय बोर्ड पर बाध्यकारी नहीं था, क्योंकि यह एक ऐसा मामला था जहाँ वह स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता था। यह भी विवाद में नहीं है कि 1995 से पहले दो दशकों या उससे अधिक समय तक, बोर्ड ने किसी निजी अनुज्ञप्तिधारी के कर्मचारियों को नहीं लिया था। इस तरह के पाठ्यक्रम पर विचार करने का कोई अवसर नहीं था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि कार्रवाई में कोई नियमितता या भविष्यवाणी या निश्चितता थी जो एक वैध अपेक्षा को जन्म दे सकती है।

20. अपीलकर्ता ने अगला तर्क दिया कि इस न्यायालय ने, कुछ वाद में, समान परिस्थितियों में अवशोषण का निर्देश दिया है। *जी. गोविंदा राजुलु बनाम आंध्र प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड,* [1986] पूरक एस.सी.सी. 651 के निर्णय पर अवलंबन है। हम नीचे पूरे निर्णय को उद्धृत करते हैं:

> "हमने मामले पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, हम निर्देश देते हैं कि आंध्र प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड के कर्मचारी जिनकी सेवाएं निगम के बंद होने के कारण समाप्त की जानी थीं, उन्हें समान नियमों और शर्तों पर सरकारी विभागों या सरकारी निगमों में सेवा में जारी रखा जाएगा। रिट याचिका तदनुसार निपटा दी गई है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है।"

उक्त आदेश का आशय, जिसके पहले कोई कारण या किसी सिद्धांत पर विचार नहीं किया गया है, यह दर्शाता है कि यह उस वाद के अजीबोगरीब तथ्यों पर संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत दिया गया आदेश था। अनुच्छेद 141 के तहत इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून बाध्यकारी है। अनुच्छेद 142 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए विशेष तथ्यों पर दिया गया कोई भी निर्देश, बाध्यकारी नज़ीर नहीं है। इसलिए, *गोविंदाराजुलु* में निर्णय उस वाद में दी गई राहत के समान राहत का दावा करने का आधार नहीं हो सकता है। *उमा देवी* (उपरोक्त) में संवैधान पीठ द्वारा इसी तरह के तर्क को नकारा गया था:

> "तथ्य यह है कि कुछ वाद में, न्यायालय ने उन वाद में शामिल कर्मचारियों के नियमितीकरण का निर्देश दिया, इसका उपयोग वैध अपेक्षा के आधार पर दावे को स्थापित करने के लिए नहीं किया जा सकता है।"

21. अब हम इस तर्क पर विचार करेंगे कि अपीलकर्ताओं न्यायसंगत विचारों पर, कार्रवाई में निष्पक्षता के सिद्धांत के आधार पर राहत के हकदार हैं। अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में इस न्यायालय के दो निर्णयों - *गुरमेल सिंह बनाम पंजाब राज्य,* [1991] 1 एस.सी.सी. 189 और *कपिला हिंगोरानी बनाम बिहार राज्य,* [2003] 6 एस.सी.सी. 1 अवलंबन।

22. *गुरमेल सिंह* (उपरोक्त) में टिप्पणियां जिन पर अवलंबन है, नीचे उद्धृत हैं:

> "यह वह जगह है, जैसा कि यहां है, हस्तांतरणकर्ता और/या अंतरिती एक राज्य या राज्य का एक अंग है, जिसे निष्पक्ष रूप से कार्य करने की आवश्यकता है और मनमाने

ढंग से नहीं (*महाबीर ऑटो स्टोर्स बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन,* [1990] 3 एस.सी.सी. 752 में फैसले को देखें और न्यायालय को यह तय करने का अधिकार है कि क्या वे नियम और शर्तें जिन पर वह एक औद्योगिक उपक्रम को सौंपने या लेने का प्रस्ताव करता है, उनमे 'कार्रवाई में निष्पक्षता' की आवश्यकता शामिल हैं और क्या उन्हें बरकरार रखा जा सकता है। हम सोचते हैं कि, निश्चित रूप से, ऐसी परिस्थितियों में इस न्यायालय के लिए राज्य सरकार और निगम के बीच व्यवस्था की समीक्षा करना और उचित निर्देश जारी करना खुला होगा। वास्तव में ऐसे निर्देश तब भी जारी किए जा सकते हैं यदि वर्तमान वाद में हस्तांतरण के तत्व निगम द्वारा राज्य के व्यवसाय या उपक्रम के पूर्ण उत्तराधिकार से कम हैं, क्योंकि जिस सिद्धांत को लागू करने की मांग की गई है वह संविधान के अनुच्छेद 14 की रूपरेखा से बहने वाला एक संवैधानिक सिद्धांत है जिसका पालन करने के लिए राज्य और निगम बाध्य हैं।"

"राज्य सरकार की ओर से यह निर्णय लेना बहुत निष्पक्ष था कि, चूंकि नलकूप निगम द्वारा संचालित किए जाएंगे, इसलिए नए कर्मचारियों की भर्ती करने के बजाय उन्हें अपीलकर्ताओं की मदद से चलाना विवेकपूर्ण होगा और यह कि सरकार को किसी भी नुकसान का बोझ उठाना चाहिए जो निगम को नलकूप चलाने के परिणामस्वरूप हो सकता है। लेकिन इतना आगे जाने के बाद, हम यह देखने में असमर्थ हैं कि सरकार ने निगम द्वारा अवशोषित किए जाने पर अपीलकर्ताओं को सरकार के साथ उनकी पिछली सेवाओं का लाभ देने से क्यों रोक दिया। इस तरह के कदम ने अपीलकर्ताओं को उनके सही देय और सेवानिवृत्ति लाभों को संरक्षित किया होता। अपीलकर्ताओं को सरकार के साथ उनकी लंबी सेवा के परिणामस्वरूप अर्जित पर्याप्त लाभों से वंचित करने में सरकार

का आचरण, हालांकि नलकूप पूरी तरह से उसके स्वामित्व वाले निगम द्वारा उसकी लागत पर चलते रहते हैं, कुछ ऐसा है जो घोर अनुचित और न्याय के विरुद्ध है। कर्मचारियों को उनके द्वारा अर्जित कुछ लाभों से वंचित करने के अलावा और कुछ हासिल न कर पाने के उद्देश्य से अपनाया गया यह रवैया निजी नियोक्ता के वाद में तो समझा जा सकता है, लेकिन राज्य सरकार की ओर से यह अनुचित है और मनमानी की बू आती है। एक आदर्श नियोक्ता के रूप में कार्य करते हुए, जो राज्य को होना चाहिए, और अधिकांश अपीलकर्ताओं की लंबी सेवा को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय में, राज्य को सरकार के साथ उनकी पिछली सेवा के लिए अपीलकर्ताओं को श्रेय देने का बोझ उठाने के लिए सहमत होना चाहिए था। इससे निगम या उसके कर्मचारियों पर किसी भी तरह से कोई असर नहीं पड़ता सिवाय - नीचे बताए गए एक सीमित सीमा तक - और, साथ ही, इसने अपीलकर्ताओं के साथ न्याय किया होता। इसलिए, हम सोचते हैं कि यह कुछ ऐसा है जिसे करने के लिए राज्य को निर्देशित किया जाना चाहिए।"

"लेकिन ऐसे वाद में जहां एक या दोनों पक्ष राज्य के अंग हैं, जिनके पास संविधान के तहत दायित्व हैं, न्यायालय के पास उपक्रम के हस्तांतरण के सभी पहलुओं पर न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। ऐसी स्थिति में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बदलाव से कोई अन्याय न हो, उचित निर्देश देना न्यायालय के लिए खुला है।"

इन टिप्पणियों को उस वाद के तथ्यों की पृष्ठभूमि में समझा जाना चाहिए। उसमें अपीलकर्ताओं राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग में नलकूप संचालक थे। राज्य ने सभी नलकूपों को राज्य द्वारा पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधित निगम को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया और परिणामस्वरूप लोक निर्माण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) में नलकूप सर्कल के संदर्भ में सभी स्थायी

पद समाप्त कर दिए गए। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एफ के संदर्भ में अधिसूचना तामील किए गए थे। जब उन अधिसूचनाओं को चुनौती दी गई, तो उन्हें इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि वे धारा 25-एफ के खंड [सी] के अनुरूप नहीं थे। राज्य सरकार ने समाप्ति के नए अधिसूचना जारी किए और उन्हें भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि वे धारा 25-एफ के खंड (बी] के अनुरूप नहीं थे। इसके बाद, राज्य सरकार ने तीसरी बार धारा 25-एफ के अनुसार सेवाओं को समाप्त करने वाले नए अधिसूचना तामील किए। तीसरे दौर के अधिसूचनाओं को भी चुनौती दी गई। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने छंटनी के अधिसूचनाओं को सही ठहराया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। लंबी खिंची मुकदमेबाजी के लंबित रहने के दौरान, नवगठित निगम ने उन्हें उसी वेतनमान का विस्तार करके उनकी सेवाएं लेने का फैसला किया, जो उन्हें राज्य सरकार की नौकरी में रहते हुए मिल रहा था। इसलिए, इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए बची एकमात्र शिकायत उसमें अपीलकर्ताओं को निगम द्वारा उनकी संबंधित नियुक्ति की तारीखों पर नए नियुक्त के रूप में माने जाने से संबंधित थी, जिससे उन्हें उनकी पिछली सेवा और वरिष्ठता के लाभ से वंचित कर दिया गया। उक्त शिकायत की जांच के संदर्भ में, इस न्यायालय ने उपरोक्त टिप्पणियां कीं। जैसा कि ऊपर देखा गया है, धारा 25-एफ एफ के तहत छंटनी को वैध पाया गया था। निगम ने स्वेच्छा से छंटनी किए गए कर्मचारियों की सेवाएं ले ली थीं। यह प्रश्न कि क्या अंतरिती या उपक्रम के खरीदार को पिछले नियोक्ता के कर्मचारियों की सेवाओं को अवशोषित करना चाहिए, यह मुद्दा नहीं था और इसलिए, उक्त निर्णय किसी सहायता का नहीं है। दूसरी ओर, *उमा देवी* (उपरोक्त) में संवैधान पीठ की निम्नलिखित टिप्पणियां प्रासंगिक हो सकती हैं:

"जाहिर है, राज्य भी आर्थिक विचारों और किसी भी सार्वजनिक रोजगार के वित्तीय निहितार्थों द्वारा नियंत्रित होता है। विभाग की व्यवहार्यता या परियोजना का अंग भी राज्य के लिए समान चिंता का विषय है। राज्य वित्तीय निहितार्थों और आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए योजना तैयार करता है। क्या न्यायालय नियमितीकरण या रोजगार में स्थायित्व पर जोर देकर राज्य पर इस प्रकृति का वित्तीय बोझ डाल सकता है, जब अस्थायी रूप से नियोजित लोगों की स्थायी या नियमित रूप से आवश्यकता नहीं है? एक उदाहरण के रूप में, हम उन सभी लोगों को स्थायी रोजगार देने के निर्देश की परिकल्पना कर सकते हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में अस्थायी या आकस्मिक रूप से कार्यरत हैं। इस तरह के निर्देश से बोझ इतना भारी हो सकता है कि उपक्रम अपने ही वजन के नीचे गिर सकता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए, न्यायालय को ऐसे निर्देशों द्वारा राज्य पर वित्तीय बोझ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ऐसे निर्देश प्रतिकूल हो सकते हैं।"

23. *कपिला हिंगोरानी* (उपरोक्त) में निर्णय एक जनहित याचिका में एक अंतरिम आदेश है। बिहार राज्य में, विभिन्न सरकारी कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने लंबे समय तक अपने कर्मकारों और अन्य कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया था, जिसके परिणामस्वरूप कई कर्मचारियों की मौत और आत्महत्याएं हुईं। उसमें याचिकाकर्ता चाहता था कि राज्य वेतन के भुगतान की जिम्मेदारी उठाए। राज्य ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया कि कंपनी की देनदारियों को निगमित आवरण हटाने के सिद्धांत या अन्यथा का सहारा लेकर राज्य पर नहीं डाला जा सकता है। इस न्यायालय ने संबंधित सरकारी कंपनियों के संबंध में सभी परिसमापन कार्यवाहियों के निपटान और कंपनी की संपत्ति और देनदारियों की जांच (पता लगाने) के लिए

एक समिति की नियुक्ति के लिए कुछ अंतरिम निर्देश जारी किए। इस न्यायालय ने राज्य सरकार को कर्मचारियों को वेतन के वितरण के लिए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 50 करोड़ रुपये की राशि जमा करने का भी निर्देश दिया। उक्त अंतरिम आदेश के दौरान, इस न्यायालय ने निम्नानुसार देखा:

> "सरकारी कंपनियां/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम "राज्य" होने के नाते भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के संदर्भ में सभी व्यक्तियों के जीवन और स्वतंत्रता का सम्मान करने के लिए संवैधानिक रूप से उत्तरदायी होंगे। इसलिए, उन्हें अपने स्वयं के कर्मचारियों के वाद में ऐसा करना चाहिए। बिहार राज्य सरकार सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए एकमात्र शेयरधारक है। हालांकि कानून में, कंपनी के देनदारों के प्रति इसकी देनदारी इसके द्वारा रखे गए शेयरों तक ही सीमित हो सकती है, लेकिन सरकारी कंपनियों पर इसके गहरे और व्यापक नियंत्रण को देखते हुए; मानवाधिकारों के प्रवर्तन और/या नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों के मामले में, राज्य का यह अतिरिक्त कर्तव्य भी है कि वह यह देखे कि ऐसे निगमों के कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन न हो।
>
> गहरे और व्यापक नियंत्रण का प्रयोग करने का अधिकार बदले में बिहार सरकार को यह देखने के लिए उत्तरदायी बना देगा कि कर्मचारियों के संबंध में जीवन और स्वतंत्रता खंड पूरी तरह से सुरक्षित है। बिहार राज्य सरकार का, इस प्रकार, सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों/निगमों के कर्मचारियों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करने का संवैधानिक दायित्व था जो भारत के नागरिक हैं। कंपनी के मामलों पर व्यापक पर्यवेक्षण के अपने अधिकार को देखते हुए इसकी एक अतिरिक्त देनदारी थी।"

राज्य के दायित्वों के संदर्भ में अंतरिम आदेश में की गई उक्त टिप्पणियां बोर्ड के तहत रोजगार मांगने के लिए किसी काम की नहीं होंगी। हम इन अपीलों में सोसाइटी या राज्य सरकार के *सापेक्ष* सोसाइटी के कर्मचारियों के अधिकारों के बारे में चिंतित नहीं हैं। हम एक विशिष्ट प्रश्न से चिंतित हैं कि क्या वे बोर्ड के तहत अवशोषण की मांग कर सकते हैं। हम इस संबंध में अनुज्ञप्ति रद्द होने के परिणामस्वरूप अनुज्ञप्तिधारी के उपक्रम को राज्य विद्युत बोर्ड में हस्तांतरित करने से संबंधित *भोला नाथ मुखर्जी बनाम पश्चिम बंगाल सरकार,* [1997] 1 एस.सी.सी. 562 में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं। उस वाद में बोर्ड ने शुरू में तत्कालीन अनुज्ञप्तिधारी के कर्मचारियों को अपनी सेवा में जारी रखने की अनुमति दी थी लेकिन बाद में ऐसी शर्तें पेश कीं जिससे वे उपक्रम को अपने अधिकार में लेने की तारीख से नए नियुक्त हो गए। विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या कर्मचारी अधिनियम की धारा 25 एफ एफ के तहत क्षतिपूर्ति के हकदार थे; और क्या अधिनियम की धारा 25 एफ एफ के तहत इस तरह के क्षतिपूर्ति के भुगतान की देनदारी हस्तांतरणकर्ता पर थी या बोर्ड पर। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कर्मचारियों को बोर्ड से किसी भी छंटनी क्षतिपूर्ति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं था, और न ही उन्हें बोर्ड द्वारा उपक्रम की खरीद के बाद समान नियमों और शर्तों पर निरंतर रोजगार में रहने का दावा करने का कोई अधिकार था। उक्त निर्णय स्पष्ट रूप से मानता है कि बोर्ड का उपक्रम के पिछले मालिक के कर्मचारियों के प्रति कोई दायित्व नहीं है।

24. इसलिए हमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है। अपील खारिज की जाती है।

के.के.टी. अपील खारिज।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।